



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2026

भाद्रपद 9, 1948 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1453/वि०स०/संसदीय/54(सं)/2026

लखनऊ, 4 अगस्त, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 4 अगस्त, 2026 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन)

विधेयक, 2026

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 संक्षिप्त नाम और कहा जाएगा। प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 8 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 8
सन् 2012 की
धारा 80 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में धारा 80 की उपधारा (8) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:—

“परन्तु यह कि यदि भूमि या उसका कोई भाग, जिसके लिए इस धारा के अधीन घोषणा की अपेक्षा की जाती है, किसी विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिसूचित क्षेत्र के भीतर आता है, और यदि ऐसी भूमि के सम्बंध में यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958, उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986, या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा, विकास अनुज्ञा या अभिन्यास योजना का अनुमोदन स्वीकृत किया गया हो, ऐसी स्वीकृति इस अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा मानी जायेगी और ऐसी जाँच जैसा कि विहित किया जाय, के उपरान्त इस आशय की प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में अनिवार्य रूप से पन्द्रह दिवस की अवधि के भीतर अभिलिखित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा के समय कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा।”

निरसन और
व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2026), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2026) एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में भू-धृति और भू-राजस्व से सम्बन्धित विधि को समेकित एवं संशोधित करने तथा उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) अधिनियमित की गयी है।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 80 के अधीन यह उपबंध है कि यदि कोई संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी धृति या उसके किसी भाग का औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों या कृषि से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये उपयोग करता है तो ऐसी कृष्येतर भूमि के उपयोग के लिए घोषणा किया जाना अपेक्षित होगा। इस उपबंध के अनुसार वर्तमान में विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरण जब किसी भूखण्ड पर कोई स्कीम या महायोजना विकसित करते हैं तो उनसे उस भूमि के कृष्येतर प्रयोजन हेतु उपयोग की घोषणा की अपेक्षा की जाती है। यद्यपि विकास प्राधिकरण तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रायः भूखण्ड पर कोई स्कीम या महायोजना विकसित किये जाने से पूर्व ही भूमि विकास या अभिन्यास योजना हेतु अनुमोदन प्रदान कर देते हैं। ऐसी स्थिति में, विकासकर्ता को भूमि के कृष्येतर उपयोग हेतु दोहरी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, विकास प्राधिकरणों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि विकास या भू-योजना का अनुमोदन सम्यक रूप से प्रदान किये जाने के पश्चात भूमि उपयोग के संपरिवर्तन और भू-अभिलेखों के नामांतरण की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 का संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 मई, 2026 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2026) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 245/XC-S-1-26-18S-2026
Dated Lucknow, August 31, 2026

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Rajasva Sanhita (Sanshodhan) Vidheyak, 2026" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 4, 2026.

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (AMENDMENT)

BILL, 2026

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows :-

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Act, 2026. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 8th day of April, 2026.

2. In the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, in sub-section (8) of section 80, the following provisos shall be *inserted*, namely: Amendment of Section 80 of U.P. Act No. 8 of 2012

“Provided that if the land, or any part thereof, for which a declaration is sought under this section, falls within the notified area of a Development Authority, an Industrial Development Authority, a Regulated Area, a Special Area Development Authority, or the Uttar Pradesh Housing and Development Board; and if, in respect of such land, as the case may be, a building permission, development permission, or approval of a layout plan has been granted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976, the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958, the Uttar Pradesh Special Area Development Authorities Act, 1986, or the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, such grant shall be deemed to constitute a declaration under sub-section (2) of Section 80 of this Act and following such inquiry as may be prescribed, an entry to this effect shall compulsorily be recorded in the revenue records within a period of fifteen days:

Repeal and
saving

Provided further that no fee shall be charged at the time of the declaration under sub-section (2) of section 80 of this Act."

3.(1) The Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance No. 6 of 2026), the Uttar Pradesh Revenue Code (Fourth Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance No. 14 of 2026) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U. P. Act No. 8 of 2012) has been enacted to consolidate and amend the law related to land tenures and land revenue in the State of Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

Under section 80 of the aforesaid Act, there is a provision that if a bhumidhar having transferable rights uses his holding or any part thereof for industrial, commercial or residential purposes, or for any purpose other than agriculture, a declaration for such non-agricultural use of land is required to be made. According to this provision, at present when Development Authorities and Industrial Development Authorities develop any scheme or master plan for a plot of land, they are required to declare the use of that land for non-agricultural purposes. However, Development authorities and Industrial Development Authorities often grant approval for land development or layout plans even before any scheme or master plan is developed for the plot of land. In such a situation, the developer has to face dual process for non-agricultural use of land.

In view of the above, it was decided to amend Section 80 of the aforesaid Act in order to simplify and streamline the process of conversion of land use and mutation of land records after the approval of land development or land plan is duly granted by the Development Authorities and Industrial Development Authorities.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Revenue Code (Fourth Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance No. 14 of 2026) was promulgated by the Governor on 23rd May, 2026.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH

Mukhya Mantri.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 485 राजपत्र-2026-(1187)-599+25+5=629 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।